आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर)

माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10–सूत्री एजेंडे के एजेंडा संख्या–6 के अनुरूप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से 2021 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भारत के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम) की स्थापना की।

इस नेटवर्क का उद्देश्य उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाना, नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना, अनुसंधान और ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता विकास को मजबूत करना है। विगत कुछ वर्षों में, आईयूआईएनडीआरआर ने निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- शिक्षाविदों और युवा वैज्ञानिकों की क्षमता का निर्माण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अनुसंधान, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- राज्यों, शिक्षाविदों और संस्थानों के बीच सहयोग और संपर्क को सुगम बनाना।

वर्तमान में, यह नेटवर्क देश भर के 327 से अधिक विश्वविद्यालयों, आईआईटी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को जोड़ता है, जो भारत के उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली में डीआरआर को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्रिय मंच के रूप में कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया (https://iuin-drr.nidm.gov.in/) पर जाएँ।

राज्यों को रणनीतिक सहयोग

एनआईडीएम राज्य एटीआई और अन्य संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जिन्हें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डीआरआर पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान चलाने के लिए चिन्हित किया गया है।



प्रकाशन



अधिक जानकारी के लिए कृपया एनआईडीएम वेबसाइट: **https://nidm.gov.** पर जाएं

आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एनआईडीएम पाठ्यक्रम

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण ढाँचे में बदलाव लाना है। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष संस्था द्वारा संचालित है। इस मिशन के तहत, आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (https://portal.igotkarmayogi.gov.in) को डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है ताकि सरकारी अधिकारियों के लिए एक व्यापक डिजिटल शिक्षण पारिस्थितिकी प्रणाली के रूप में कार्य किया जा सके। यह निरंतर व्यावसायिक विकास को सुगम बनाने, शासन के लिए भूमिका–आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और संस्थागत प्रभावशीलता में सुधार के लिए संरचित शिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

स्थान एवं सुविधाएं

एनआईडीएम के देश में दो परिसर हैं। दिल्ली और आंध्र प्रदेश स्थित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:

- प्रशिक्षण एवं सम्मेलन कक्ष
- सुसज्जित पुस्तकालय
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आवास एवं भोजन की व्यवस्था

दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गन्नावरम मंडल के कोंडापवुलुरु गाँव में स्थित है। यह परिसर पूरे वर्ष सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के आमने–सामने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि/अधिकारी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें



एनआईडीएम दक्षिणी परिसर

https://nidm.gov.in/PDF/trgcal/Trg_Cal_2024&25-pdf

एनआईडीएम दिल्ली परिसर

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर



nidm

Resilient India - Disaster Free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नंबर 15, पॉकेट-3, ब्लॉक-बी, सेक्टर-29, रोहिणी, दिल्ली - 42

फोन न. : 011-20873412 • वेबसाइट : https://nidm.gov.in

/ nidmmhaindia / nidmmhaindia

/ nidmindia / nidmmhaindia / nidmmhaindia

संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 30.10.2006 को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और डेटाबेस के विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने, आपदा प्रबंधन नीतियों की तैयारी में सहायता करने, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रोकथाम तंत्र और शमन उपायों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 16 अक्टूबर 2003 को कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से पुनर्नामित, एनआईडीएम सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को विकसित और बढ़ावा देकर एक आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने के अभियान की ओर निरंतर अग्रसर है।



श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 15 से 26 सितंबर, 2025 तक दिल्ली स्थित एनआईडीएम में आईटीईसी साझेदार देशों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन पर आयोजित चौथे व्यापक पाठ्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, इसके दो निकाय हैं, संस्थान निकाय और शासी निकाय। संस्थान निकाय में 42 सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, संबंधित राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के प्रमुख, प्रख्यात वैज्ञानिक और डीआरआर विशेषज्ञ शामिल हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा–निर्देशों के अधीन कार्य करता रहा है। संस्थान के शासी परिषद् में 14 हैं, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में गृह सचिव होते हैं।

चूँकि एनडीएमए के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसलिए गृह सचिव शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। कार्यकारी निदेशक संस्थान का दैनिक प्रशासन चलाते हैं। संस्थान में निम्नलिखित शैक्षणिक प्रभाग हैं:

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति प्रभाग (डीआरआरडी)
- भौगोलिक–मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)
- समुत्थानशील संरचना प्रभाग (आरआईडी)
- सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)

उपर्युक्त प्रभागों के अलावा, संस्थान में 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।



श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, एनडीएमए द्वारा चौथे व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम को संबोधित किया गया, जो आईटीईसी साझेदार देशों के लिए एनआईडीएम द्वारा 15 – 26 सितंबर 2025, दिल्ली में आयोजित किया गया।

कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, संस्थान को अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

क) आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, अनुसंधान और प्रलेखन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ख) आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन।

ग) राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

घ) विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

ड़) राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना।

च) शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सामग्रियों का विकास।

छ) कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु–जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना।

ज) उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों को आयोजित करना और सुगम बनाना।

झ) पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख–रखाव आदि।

ञ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना।

ट) केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन।

प्रमुख क्षेत्र

प्रशिक्षण

आमने–सामने प्रशिक्षण: एनआईडीएम विभिन्न विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में परिसर के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आमने–सामना कार्यक्रमों के अलावा, एनआईडीएम मिश्रित मोड में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।

वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण: संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशिष्ट विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उपयोगकर्ता पंजीकरण कर सकते हैं और ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

स्व–अध्ययन पाठ्यक्रम: संस्थान ने वेब–आधारित स्व–अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिन्हें कहीं से भी दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है और कभी भी उपयोग किया जा सकता है। ये पाठ्यक्रम मुख्यतः आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से ज्ञान साझा करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं।

अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली प्रमुख आपदाओं का दस्तावेजीकरण करता है ताकि उनके प्रबंधन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सके और उन्हें प्रशिक्षण कक्षाओं और सिमुलेशन अभ्यासों के लिए केस स्टडीध्संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सके।

एनआईडीएम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के साथ–साथ, राष्ट्रीय स्तर के दिशा–निर्देशों, नीतियों और योजनाओं आदि की तैयारी में गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को भी सहायता प्रदान करता है। एनआईडीएम राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों)



एनआईडीएम में 01 से 14 सितंबर तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय कार्यकारी निदेशक, श्री सफी एहसन रिजवी द्वारा 03 सितंबर, 2025 को रोहिणी परिसर, दिल्ली में किया गया।